यूपी:भाजपा-बसपा छोड़ सपा में जाने की मची होड़

सुशील मानव

किसी चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिये दूसरे दलों के नेताओं, और दलों को अपने पाले में लाने का जो खेल अब तक भाजपा दूसरे दलों पर खेलती आ रही थी वही खेल उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ शुरू हो गया है। कई भाजपा नेता योगी की नाव डूबने से पहले ही सुरक्षित ठिकाने की तलाश में दूसरे दलों में जाने लगे हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी फिलहाल दल बदलुओं के लिये हॉट केक बना हुआ है।

अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में बसपा के आठ बाग़ी विधायक, चार विधायकों वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कांग्रेस के एक पूर्व विधायक और पूर्व सांसद के अलावा बीजेपी के एक विधायक अपनी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये थे। 28 अक्टूबर को एक बड़ी जनसभा में विधान सभा के चार विधायकों वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को राजभर समाज का वोट दिलाने की क़सम खाई और पश्चिम बंगाल की तर्ज़ पर "खेला होबे" के नारे से मिलता हुआ "खदेड़ा होबे" का नारा दिया।

भाजपा की सहयोगी पार्टी के अपने पाले में लाने से गदगद अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में, "भाजपा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है और सपा ने उस पर सिटकनी लगा दी है।" गौरतलब है कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक पूर्वांचल में कई सीटों पर भाजपा को इस गठबंधन से नुक़सान पहुँचने की बात कह रहे हैं।

वहीं आज 9 नवंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व और समाजवादी पार्टी की नीतियों पर आस्था जताते हुए भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा और जनता दल लोकतांत्रिक के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने वर्ष 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उम्मीद जताई कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह के साथ फतेह मोहम्मद, नंदलाल पटेल, धीरेन्द्र राय, कपिल खरवार, रामजन्म पटेल, दीप नारायण पटेल, जवाहिर अगरिया, राम कुमार खरवार, गोपाल गूजर, नारायण बियार सहित 35 लोग सपा में शामिल हुए। जनता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राम भरोसे सिंह ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने अब तक के कार्यकाल में प्रदेश में सिर्फ अव्यवस्था और अराजकता फैलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। उसका आचरण और प्रकृति दंगाई किस्म का है। नफ़रत का तानाबाना फैलाने के साथ समाज को बांटने और विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ाने में ही भाजपा लगी रहती है। झूठ के लिए ही उसका मंथन, निरन्तर चलता रहता है।

इससे पहले शनिवार 30 अक्टूबर को बसपा के 6 बाग़ी विधायक समाजवादी से जुड़े। असलम राइनी (भिनगा-श्रावस्ती), असलम अली चौधरी (धौलाना-हापुड़), मुजतबा सिद्दीक़ी (प्रतापपुर-इलाहाबाद), हाकिम लाल बिंद (हंडिया-प्रयागराज), हरगोविंद भार्गव (सिधौली-सीतापुर), और सुषमा पटेल (मुंगरा-बादशाहपुर) अब बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर से विधायक राजेश राठौड़ ने भी सपा की सदस्यता ली। सपा से जुड़ रहे नेताओं ने हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपसभापति के चुनाव में सपा के प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को वोट दिया था।

दरअसल शुक्रवार 29 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए नारा दिया "मेरा परिवार, भाजपा परिवार।" इसके ठीक अगले ही दिन उस परिवार के एक सदस्य और भाजपा के सीतापुर सदर से विधायक राकेश राठौड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये। जिस पर चुटकी लेते हुये अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को अपना नारा बदल कर, "भाजपा परिवार भागता परिवार" कर लेना चाहिए।

इससे पहले 24 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष रविवार को बस्ती से ब्लाक प्रमुख बहादुरपुर राम कुमार अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा छोड़कर सपा की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी की नीतियों व अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए रायबरेली के भाजपा नेता व पूर्व विधायक शिव गणेश लोधी के पुत्र राहुल लोधी के साथ रामऔतार, अजय कुमार शुक्ल, उमाशंकर लोधी, राजेश कुमार त्रिपाठी साथियों सहित सपा में शामिल हुए। रायबरेली स्थित न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंधक डा. शशिकांत शर्मा अपने समर्थकों डा. अरुण चौधरी, डा. एसके पांडेय, डा. नीरज सिंह, शीला सिंह, अजीत चौधरी कन्नौजिया, मो. असद, अमरजीत सिंह के साथ सपा में शामिल हुए। राहुल विश्वकर्मा सदस्य जिला पंचायत महराजगंज बसपा छोड़ शामिल हुए।

इससे पहले 3 अक्टूबर रविवार को पूर्व सांसद तथा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव वीर सिंह एडवोकेट (मुरादाबाद), पूर्व विधायक अजीम भाई (फिरोजाबाद) तथा प्रमुख समाजसेवी एवं (भाजपा) युवा क्षेत्रीय मंत्री विनोद मिश्र (जौनपुर) ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।

1 अक्टूबर को पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा रिजवान ,राम प्रकाश कुशवाहा, पूर्व विधायक, घाटमपुर (बसपा), पूर्व जिलाध्यक्ष रीता कुशवाहा (बसपा), विनोद चतुर्वेदी (कांग्रेस के पूर्व विधायक) और उनके कई सहयोगी, मनोज तिवारी (कांग्रेस), सागर शर्मा और उनके 15 साथी (कांग्रेस) अपना दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओंकार सिंह, भाजपा के पिछड़ा वर्ग विंग के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य ने सपा की सदस्यता ग्रहण की थी।

भारतीय जनता पार्टी के सात विधायक और बसपा के छह विधायक लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में खुद को असहज महसूस करने वाले कई विधायक और कई नेता कहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इन नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी सुनी नहीं जा रही है। जब अपने क्षेत्र की जनता की आवाज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करते थे तो उनको दरकिनार कर दिया जाता था। इन विधायकों का कहना है कि विधानसभा के चुनाव में वह अपनी जनता के पास किस मुंह से जाएंगे। क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान तो हुआ ही नहीं। ऐसे में उनके पास दूसरी पार्टी में जाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है।

गंभीर आरोपों से घिरे समीर वानखेड़े पर पूरा सिस्टम क्यों मेहरबान है?

अनिल जैन

मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर दाउद वानखेड़े और उनके गैर सरकारी सहयोगियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। उनके खुलासों से सिर्फ समीर वानखेड़े ही नहीं बल्कि समूचे एनसीबी की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिन पर एनसीबी के आला अधिकारी तो मौन हैं ही, केंद्र सरकार की चुप्पी भी हैरान करने वाली है। सरकार के ढिंढोरची की भूमिका निभा रहे मीडिया में भी उन सवालों की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि नवाब मलिक के पास वानखेड़े और एनसीबी के बारे में इतनी जानकारी कहां से आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि नवाब मलिक का दामाद ड्रग मामले में जेल में है, इसलिए उसे बचाने के लिए वे समीर वानखेड़े और एनसीबी को निशाना बना रहे हैं।

यह सही है कि नवाब मलिक का दामाद जेल में है, लेकिन उसका मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं कि मलिक अपने दामाद को बचाने के लिए यह सब कर रहे हैं। अगर यह मान भी लिया जाए कि वे अपने दामाद को बचाने के लिए समीर वानखेड़े को लेकर खुलासे कर रहे हैं और एनसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल यह भी उठता है कि पूरा सिस्टम और सत्तारूढ़ दल गंभीर आरोपों से घिरे समीर वानखेड़े को बचाने में क्यों जुटा हुआ है? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस और अन्य भाजपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े के बचाव में क्यों उतर आए हैं?

यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि वानखेड़े के खिलाफ कई गंभीर आरोप होने के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद अपनी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर वानखेड़े हाई कोर्ट पहुंच गए। मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें राहत भी दे दी और कहा कि उनको किसी भी मामले में गिरफ्तार करने से तीन दिन पहले नोटिस देना होगा। अदालत का इस आदेश का आखिर क्या मतलब है? सवाल है कि आपराधिक मामलों में किसी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस क्या इसी तरह नोटिस देती है?

वानखेड़े को राहत देने वाली अदालत को क्या यह मालूम नहीं है कि उसने इसी तरह की राहत मनी लांड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को भी दी थी और वे इसका फायदा उठा कर फरार हो गए हैं। समझा जाता है कि वे भी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आदि हाईप्रोफाइल आर्थिक अपराधियों की तरह सिस्टम की मदद से देश छोड़ कर भाग गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी परमबीर सिंह के देश से भाग जाने का अंदेशा जताया है। इसलिए सवाल उठता है कि अब अगर वानखेड़े भी अदालत से मिली राहत का फायदा उठा कर परमबीर सिंह की तरह देश से निकल भागेंगे तो कोई क्या कर लेगा?

सरकार तो वानखेड़े पर पहले से ही मेहरबान है। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद अपने दलित होने का फर्जी प्रमाणपत्र बनवा कर सरकारी नौकरी हासिल की है। उन पर बेकसूर लोगों को ड्रग संबंधी मामलों में फंसा कर झूठे मुकदमे कायम करने और पैसे वसूलने के आरोप भी हैं। इसके अलावा भी उन पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की बजाय एनसीबी के ही विजिलेंस विभाग से कराई जा रही है।

यही नहीं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने तो बिना किसी जांच पड़ताल के ही घोषित कर दिया कि वानखेड़े का जाति प्रमाणपत्र फर्जी नहीं है और वे दलित ही हैं। अनुसूचित जाति आयोग वानखेड़े पर लग रहे आरोपों को दलित प्रताड़ना का मामला मान कर नोटिस जारी कर रहा है। सरकार ने हद तो यह कर दी है कि क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले की जांच एसआईटी को सौंप दिए जाने के बावजूद वानखेड़े को इस जांच से अलग नहीं किया है जबकि वे खुद इस मामले की जांच में फंसे हुए हैं। कितनी हैरान करने वाली बात है कि उन पर उगाही करने के लिए इस ड्रग्स पार्टी में छापा मारने का आरोप लगा है और वे खुद ही इस मामले की जांच करते रहेंगे।

मोदी सरकार और भाजपा ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के मामले में तो कई नए आयाम पेश किए हैं, वह अपराध और अपराधियों के सरकारीकरण की नई इबारत लिखने जा रही है।

क्रूरतापूर्ण मजाक की भी एक सीमा होती है योगी जी!

कृष्णकांत

वे बंदूक और ठोको नीति का सहारा लेकर अपराधियों को कंट्रोल करने निकले थे। न अपराध कंट्रोल हुआ, न अपराधी कंट्रोल में आए, न पुलिस कंट्रोल में रह गई। हर दिन यूपी पुलिस के कारनामे भयावह हैं। उत्तर प्रदेश अब ऐसा प्रदेश है, जहां रोज कानून व्यवस्था का जनाजा निकाला जाता है।

उ.प्र. पुलिस के अनुसार यही वो टोटी है जिस पर अल्ताफ ने झूलकर आत्महत्या की।

आप खुद सोचिए कि डेढ़ दो फुट ऊंचाई पर लगी टोंटी से कोई 22 साल का आदमी लटक कर आत्महत्या कैसे कर सकता है ? लेकिन यूपी पुलिस यह अश्लील और क्रूर कहानी धड़ल्ले से सुना सकती है, क्योंकि खुद पुलिस की निगाह में कानून का कोई इकबाल नहीं बचा है। कासगंज में अल्ताफ की गैर न्यायिक हत्या न पहली है, न आखिरी।

क्राइम केसेज में हम बचपन से सुनते आए हैं कि आत्महत्या के मामले में अगर कहीं से भी पैर जमीन पर या किसी सतह पर छू जाने की गुंजाइश रहती है तो आत्महत्या की थ्योरी को नकार दिया जाता है। क्योंकि जान निकलना आसान नहीं होता। आदमी छटपटाकर पैर जमीन पर रख देता है। लेकिन यूपी पुलिस कुछ ऐसा दावा कर रही है कि आदमी ने बिस्तर पर सोते - सोते या जमीन पर बैठे-बैठे फांसी लगा ली।

कभी कासगंज, कभी आगरा, कभी गोरखपुर हर शहर हर थाने की यही कहानी है। आंकड़े गवाही देते हैं कि 'यूपी नंबर 1' का नारा देने वाली बीजेपी के शासन में

यूपी और किसी में नंबर वन 1 हो या न हो, लेकिन हिरासत में मौत के मामलों में उत्तर प्रदेश यकीनन नंबर वन है।

इस साल 27 जुलाई को लोकसभा में पूछा गया कि देश में पुलिस और न्यायिक हिरासत में कितने लोगों की मौत हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के सहारे बताया कि हिरासत में मौत के मामलों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उत्तरप्रदेश में पिछले तीन साल में 1,318 लोगों की पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौत हुई है।

यूपी की पुलिस व्यवस्था अपने आप में कानून व्यवस्था और रूल ऑफ लॉ की बर्बादी की जिंदा कहानी है, जहां पुलिस यौन हिंसा से पीड़ित किसी महिला को पेट्रोल डालकर जला सकती है, आधी रात को कमरे में घुसकर किसी को मार सकती है, हिरासत में किसी को पीट-पीट कर उसकी जान ले सकती है।

नारा है कि उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त हो गया है, लेकिन असल कहानी ये है कि जिस पुलिस पर अपराध से निपटने और जनता को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, वह पुलिस खुद अपराधी की भूमिका में है। शुक्र मनाइए कि ऐसी व्यवस्था से आपका पाला न पड़े।

दुनिया में नाकारा प्रशासन का इससे घटिया उदाहरण मौजूद नहीं है जहां खुद पुलिस ही कंट्रोल में न रह जाए।